

Ease of Doing Business in India



Unit : 4
Course Code: CMRC3036
Course Title: International Business
Programme : B.Com.(H)

Avneesh Kumar

Assistant Professor of Commerce, Mahatma Gandhi Central University, Motihari

Introduction

परिचय

- “An entrepreneur in a low-income economy typically spends around 50% of the country’s per-capita income to launch a company, compared with just 4.2% for an entrepreneur in a high-income economy. It takes nearly six times as long on average to start a business in the economies ranked in the bottom 50 as in the top 20.”*

(कम आय वाली अर्थव्यवस्था में एक उद्यमी आम तौर पर एक कंपनी को लॉन्च करने के लिए देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50% खर्च करता है, जबकि एक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था में एक उद्यमी देश की प्रति व्यक्ति आय का केवल 4.2% ही खर्च करता है। शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में नीचे की ओर से क्रमबद्ध 50 अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसाय शुरू करने में औसतन लगभग छह गुना लंबा समय लगता है।)

- The statement unravels how the low-income economies remain trapped in their self-managed inefficient system of governance which hinders their growth and keeps them non-competitive with other well-managed economies.

(यह कथन उजागर करता है कि कैसे कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं शासन की स्व-प्रबंधित अक्षम प्रणाली में फंसी रहती हैं जो उनके विकास में बाधा बनती हैं और उन्हें अन्य अच्छी तरह से प्रबंधित अर्थव्यवस्थाओं के साथ गैर-प्रतिस्पर्धी रखती हैं।)

• * 26 April, 2020
Source: Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank.

Ease of Doing Business in India

भारत में व्यापार करने की आसानी



- India's ease of doing business ranking improved from 130 in 2016 report to 63 in 2020 report. China ranks 31 in Doing Business 2020 report out of 190 economies.

(2016 की रिपोर्ट में भारत की सुगमता व्यापार रैंकिंग 130 से सुधरकर 2020 रिपोर्ट में 63 हो गई। चीन 190 अर्थव्यवस्थाओं में से डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में 31 वें स्थान पर है।)

- The Ease of Doing Business (EoDB) ranking system (established by the World Bank Group) is based on aggregates information from 10 areas of business regulation: Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Getting Electricity, Registering Property, Getting Credit, Protecting Minority Investors, Paying Taxes, Trading across Borders, Enforcing Contracts, Resolving Insolvency.

(ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग प्रणाली (विश्व बैंक समूह द्वारा स्थापित) व्यापार विनियमन के 10 क्षेत्रों से एकत्रित जानकारी पर आधारित है: एक व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशक की रक्षा करना, कर भुगतान, सीमाओं के पार व्यापार, संविदा को लागू करना, दिवालियापन का समाधान करना।)

Ease of Doing Business in India

भारत में व्यापार करने की आसानी



- India is among the 10 economies who have improved their business environment the most. (भारत उन 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिन्होंने अपने कारोबारी माहौल को सबसे बेहतर बनाया है।)

TABLE O.2 The 10 economies improving the most across three or more areas measured by *Doing Business* in 2018/19

Economy	Rank	Change in DB score	Reforms making it easier to do business									
			Starting a business	Dealing with construction permits	Getting electricity	Registering property	Getting credit	Protecting minority investors	Paying taxes	Trading across borders	Enforcing contracts	Resolving insolvency
Saudi Arabia	62	7.7	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
Jordan	75	7.6					✓		✓			✓
Togo	97	7.0	✓	✓	✓	✓	✓					
Bahrain	43	5.9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tajikistan	106	5.7	✓				✓			✓		
Pakistan	108	5.6	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Kuwait	83	4.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
China	31	4.0	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
India	63	3.5	✓	✓						✓		✓
Nigeria	131	3.4	✓	✓	✓	✓				✓	✓	

Source: *Doing Business* database.

Ease of Doing Business in India

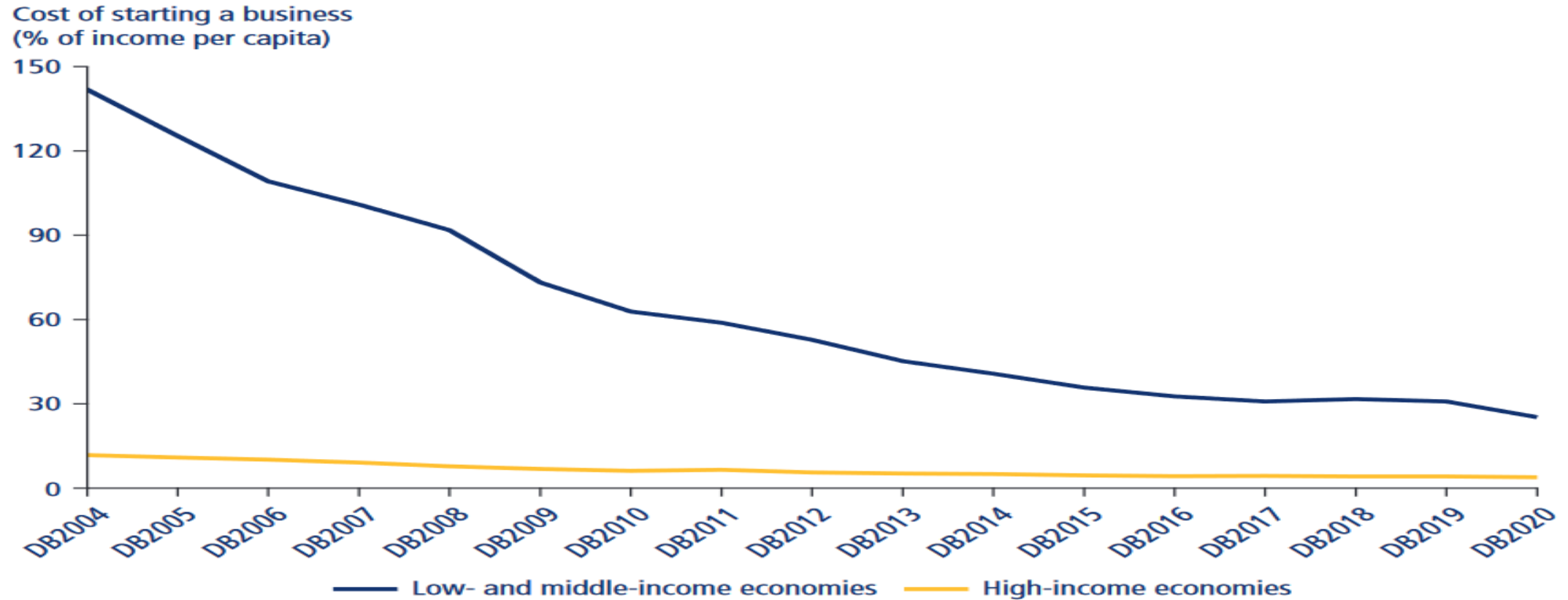
भारत में व्यापार करने की आसानी



- For three consecutive years India has figured in the list of 10 most improved economies. Given the huge size of India's economy, the reform efforts undertaken during past 3-4 years are commendable. (लगातार तीन वर्षों से भारत 10 सबसे बेहतर अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल है। भारत की अर्थव्यवस्था के विशाल आकार को देखते हुए, पिछले 3-4 वर्षों के दौरान किए गए सुधार के प्रयास सराहनीय हैं।)
- Prime Minister Narendra Modi's "Make in India" campaign has to a great extent been successful in attracting more foreign investment in manufacturing. Those states who have been maintaining a better business environment in India have largely benefitted from the campaign.
- (प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का "मेक इन इंडिया" अभियान काफी हद तक विनिर्माण क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है। जो राज्य भारत में बेहतर कारोबारी माहौल बनाए हुए हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान से लाभ मिला है।)

Cost of Starting a Business in Developing Economies

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक व्यवसाय शुरू करने की लागत (2004-2020)



Source: Doing Business database.

Note: The sample comprises 145 economies.

Initiatives of the Government of India

भारत सरकार की पहल

- Simplification in the procedures of registering a new business.
(एक नए व्यवसाय को पंजीकृत करने की प्रक्रियाओं में सरलीकरण।)
- Speeding up the process of getting Construction Permits.
(निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति देना)
- e-Sanchit, 'Indian Customs Single Window Project' etc. to facilitate trade.
(व्यापार की सुविधा के लिए ई-संचित, 'भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की परियोजना' आदि।)

Initiatives of the Government of India

भारत सरकार की पहल

- Establishment of Commercial Courts and National Judicial Data Grid for enforcing contracts and for faster resolution of commercial disputes.
(अनुबंध लागू करने और वाणिज्यिक विवादों के तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड की स्थापना।)
- Simpler and faster process of getting electricity connection for business.
(व्यापार के लिए बिजली कनेक्शन लेने की सरल और तेज प्रक्रिया)
- Various digital initiatives at registrar and sub-registrar offices for registration of property.
(संपत्ति के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में विभिन्न डिजिटल पहल)

Initiatives of the Government of India

भारत सरकार की पहल

- Enactment of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 for better handling corporate insolvency.
(कॉर्पोरेट दिवाला को बेहतर तरीके से संभालने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का अधिनियमन)
- Reduction in corporate tax rate for existing and new companies.
(मौजूदा और नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर में कमी)
- Goods and Service Tax implementation
(माल और सेवा कर कार्यान्वयन)

What other things need to be done?

किन अन्य चीजों को करने की आवश्यकता है?

- Law & order situation in many backward regions of India need to be improved for more business startups.

(और अधिक व्यावसायिक स्टार्टअप के लिए भारत के कई पिछड़े क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है)

- Commerce education should be linked with business ventures and training.

(वाणिज्य शिक्षा को व्यावसायिक उद्यम और प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए)

- Research in Commerce should be more focused upon setting up incubation centers for budding entrepreneurs.

(वाणिज्य में अनुसंधान को नवोदित उद्यमियों के लिए उद्भव केन्द्र स्थापित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए)



आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ।
Let noble thoughts come to us from every side.